बिजली क्यों महंगी हो रही है?

नालायकों और बेईमानों से और आशा भी क्या हो सकती है?

पानीपत (म.मो.) गत तीसियों-चालीसों बरस से चल रहा बिजली संकट कहीं से हल होता नज़र नहीं आ रहा। बिजली के दाम लगातार बढ़ाये जाने व नये-नये पावर प्लांट लगाये जाने के बावजूद यह संकट दिन-दूणा-रात-चौगुणा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में जो भी मुख्यमंत्री आता है, वह पिछली सरकार को इस संकट के लिए ज़िम्मेदार बता कर अगले पांच साल में इसे हल करने का आश्वासन दे देता है। लेकिन वास्तव में संकट कहीं से भी घटने के आसार नहीं दिखते। मौजूदा हुड्डा सरकार आंकड़ों के आधार पर बिजली संकट को अगले दो-तीन वर्ष में हल करने का दावा कर रही है जो कि एकदम खोखला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पानीपत के 110 गुणा 4, 210 गुणा 2, 250 गुणा 2 यानी कुल 1360 मेगावाट, यमुनानगर के 300 गुणा 2 = 600 तथा खेदड़ का 600 मेगावाट के प्लांट इस समय चालू हैं तथा 600 मेगावाट दूसरा यूनिट भी जल्द चालू होने की बात कही जा रही है। इनके अलावा छोटे-मोटे हाइडल प्रोजेक्टों से उपलब्ध बिजली को मिला कर राज्य की कुल बिजली आपूर्ति 2630 मेगावाट बनती है। इसमें भाखड़ा तथा मुझेड़ी से प्राप्त होने वाली बिजली शामिल नहीं है। झज्जर में लगाये जाने वाले प्लांट से 500 गुणा 3 यानी 1500 मेगावाट बिजली बनेगी जिसका आधा यानी 750 मेगावाट हरियाणा को मिलेगा। यह प्लांट हरियाणा सरकार की दखलंदाजी एवं चोरबाज़ारी से पूर्णतया मुक्त रह कर एनटीपीसी द्वारा चलाया जायेगा, इसलिए पूरी आशा है कि यह प्लांट वास्तव में ही हरियाणा को 750 मेगावाट दे पायेगा।

लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा संचालित उपरोक्त प्लांटों में से एक भी प्लांट अपनी निर्धारित एवं घोषित क्षमता का न तो उत्पादन कर रहा है और न ही कभी करेगा, और ना ही अपनी निर्धारित (25 वर्षों की) आयु तक चल पायेगा। आज के दिन राज्य सरकार द्वारा संचालित ये सभी प्लांट अपनी उत्पादन क्षमता का मात्र 68.47 प्रतिशत यानी 2630 मेगावाट की जगह मात्र 1788.40 मेगावाट ही बिजली उत्पादन कर रहे हैं। सरकारी तौर-तरीकों को देखते हुए इसमें कोई सुधार की भी गुंजाइश नहीं दिखती, बल्कि उत्पादन का प्रतिशत दिन-ब-दिन घटता ही जायेगा, क्योंकि अभी तो ये प्लांट नये तथा गारंटी काल में हैं और ज्यों-ज्यों ये प्लांट पुराने होते जायेंगे, इनकी उत्पादकता का स्तर गिरना अवश्यंभावी है।

यहां महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या सभी प्लांटों की उत्पादकता ऐसी ही होती है? नहीं। यह हाल केवल उन प्लांटों का होता है जिन्हें नालायक और बेईमान लोग चलाते हैं। जिनको प्लांट चलाने की बजाय इसे लूटने-खाने में अधिक दिलचस्पी होती है। उदाहरणार्थ फरीदाबाद के 60 मेगावाट के 3 थर्मल प्लांटों से चार साल पहले बिड़ला ने भी रेणु सागर में इसी डिज़ाइन के पांच प्लांट लगाये थे जो आज भी अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन दे रहे हैं और अभी कई साल और भी चलेंगे, जबकि यहां के तीनों यूनिट जय बोल चुके हैं। कारण? कारण वही नालायकी एवं चोरबाज़ारी। उनके प्लांट कभी ट्रिप नहीं होते, केवल निर्धारित शटडाऊन होता है, जिसके दौरान प्लांट पूरी तरह फ़िट कर दिया जाता है। इस दौरान 100 रुपये की जगह 100 रुपये का ही सामान लगता है, जबकि यहां निर्धारित शटडाऊन की बजाय आये दिन ट्रिपिंग होती रहती है जिसे ठीक करने के नाम पर 100 का सामान लगा कर दस हज़ार का बिल बनाया जाता है।

जनता के पैसे को धुएं में उड़ाते प्लांट

ट्रिपिंग का अर्थ होता है कि चलते प्लांट में कुछ गड़बड़ी के कारण एकदम से प्लांट का बंद हो जाना, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन तो बंद होता ही है, इसके अलावा प्लांट को ठीक करना व पुन: चलाना बहुत ही महंगा पड़ता है। किसी भी चलते प्लांट में नियमानुसार ट्रिपिंग होनी नहीं चाहिए। यह केवल तभी होती है जब प्लांट का संचालन एवं रख-रखाव ठीक न हो। जाहिर है, जब नालायक एवं बेईमान लोग जिस प्लांट का संचालन व रख-रखाव करेंगे तो वहां तो ट्रिपिंग तो होगी ही। टाटा, बिड़ला तथा अन्य प्राइवेट लोगों के प्लांटों की तो बात ही छोड़ो, एनटीपीसी जो भारत सरकार का उपक्रम है, में भी ऐसे प्लांट मिल जायेंगे जहां कभी ट्रिपिंग नहीं होती जबकि हरियाणा सरकार के किसी न किसी प्लांट में आये दिन ट्रिपिंग होती रहती है। ऐसे भी उदाहरण हैं जब एक ही यूनिट एक माह में दस बार तक ट्रिप हो जाती है। पानीपत की सबसे नई यूनिट नंबर-8 है जो 250 मेगावाट की अत्याधुनिक यूनिट है। अप्रैल माह में यह सात बार तथा 22 मई तक तीन बार ट्रिप हो चुकी है। इन सभी ट्रिपिंग्ज के पीछे हर बार एक ही कारण रहा - ईंधन का न पहुंचना।

प्रत्येक यूनिट में एक एसई रैंक का अधिकारी केवल ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए तैनात होता है। इसे एसई फ्यूल कहते हैं। इसके मातहत जरूरत से अधिक स्टाफ़ भी तैनात रहता है तथा टेकपरो नाम की एक कंपनी को भी करोड़ों वार्षिक के ठेके पर इसी एसई के मातहत रखा जाता है जो यूनिट के बॉयलर में ईंधन की आपूर्ति निर्बाध रूप से करे। यद्यपि करोड़ों रुपया देने के बाद सरकार का कोई दायित्व नहीं रह जाता कि कोई सरकारी कर्मचारी वही काम करे जिसका ठेका कंपनी को दे दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद 90 सरकारी कर्मचारी इसी काम में 'जुटे' हैं। जाहिर है, ठेकेदार कंपनी इस मेहरबानी के बदले सरकारी अफ़सरों की भरपूर सेवा करती है। मोटा कमीशन देने के अलावा सरकार के चहेते एवं नाकारा लोगों को भी ठेकेदार कंपनी काम पर लगाती है। ऐसे नाकारा लोगों में सबसे बड़ा नाम है मिगलानी का, जो चार वर्ष पहले एक्सईएन के पद से रिटायर हो चुका था, उसे कंपनी ने एक लाख मासिक पर अपना साइट इंजीनियर नियुक्त कर रखा है। यद्यपि टेकपरो नामक इस कंपनी तथा एसई फ्यूल के जिम्मे केवल एक ही काम रहता है कि वह बॉयलर को ईंधन आपूर्ति करता रहे जिससे उसकी आग न बुझे। लेकिन इसके बावजूद अकेले अप्रैल माह में यूनिट नंबर-8 का सात बार ट्रिप हो जाना और वह भी ईंधन की आपूर्ति न हो पाने की वजह से, सरकारी कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। विशेषज्ञों के अनुसार बार-बार ट्रिप होने की वजह से बॉयलर भी क्षतिग्रस्त हो गया जिसके चलते 22 मई को यह इकाई पूरी तरह बंद कर के ओवरहालिंग के लिये दे दी गई है। इसमें तीन से चार सप्ताह का समय और करोड़ों का खर्च लगेगा, बिजली उत्पादन ठप रहेगा, वह अलग से। ख़बर लिखते-लिखते पता चला कि खेदड़ (हिसार) वाले 600 मेगावाट प्लांट जो गत लगभग डेढ़ माह से परीक्षण पर चल रहा था, उसके बॉयलर की ट्यूबों के सारे जोड़ खुल गये हैं। रिलायंस कंपनी द्वारा चीन निर्मित सामान से लगाये जा रहे इस प्लांट की 600 मेगावाट की दो यूनिटों में से अभी पहली का ही परीक्षण चल रहा था। परीक्षण के दौरान अभी इस पर 300 मेगावाट का ही लोड डाला गया था कि बॉयलर बोल गया। आधे लोड पर ही बॉयलर का बोल जाना सिद्ध करता है कि या तो माल घटिया लगा है या कार्य कुशलता घटिया स्तर की रही है। दोनों ही कारण भी संभव हो सकते हैं। संदर्भवश यह जान लेना भी जरूरी है कि प्लांट लगाने का काम बेशक रिलायंस कंपनी कर रही है, लेकिन करवाने वाली तो हरियाणा सरकार है जो रिलायंस कंपनी के हर काम की पैमाइश के हिसाब से पेमेंट करती आ रही है और कुल 3775.4 हज़ार करोड़ रुपये का एक बड़ा भाग अदा भी किया जा चुका है। जाहिर है, जब सरकार काम के साथ-साथ पेमेंट कर रही है तो किये जाने वाले काम का मूल्यांकन व निगरानी करना भी तो सरकार का काम है। सरकार ने इसी काम के लिये अफ़सरों की भारी-भरकम फ़ौज वहां लगा भी रखी है, लेकिन सबके सब नाकारा व नालायक सिद्ध हो रहे हैं। अतंत: होना यह है कि रिलायंस वाले लीपापोती करके प्लांट हरियाणा सरकार को चेप जायेंगे। मुख्यमंत्री बड़े-बड़े विज्ञापन छपवा कर अपनी उपलब्धि का बखान करते हुए उसका उद्घाटन करेंगे, राज्य की जनता को समर्पण करेंगे। जनता बिना कुछ सोचे-समझे तालियां बजाते हुये बिजली संकट से निजात पाने की आशा करेगी। परंतु जब प्लांट चलेगा, आये दिन ट्रिप होगा, बॉयलर की ट्यूबें लीक होंगी तो उसे महसूस होगा कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। इसका ताजा तरीन उदाहरण यमुना नगर का प्लांट है जिसके उद्घाटन के नाम पर अपनी राजनैतिक बाजीगरी दिखाते हुये मुख्यमंत्री हुड्डा ने करीब दो वर्ष पहले राज्य भर के पंचों-सरपंचों को यमुना नगर बुला कर प्लांट का जनता को समर्पण किया था। आज उसी प्लांट की दुर्दशा देखने लायक है। खेदड़ या पानीपत प्लांट के जो उदाहरण दिये गये हैं, ये तो पूरे घोटाले के कण मात्र हैं। वास्तव में हर यूनिट में और हर स्तर पर नाकारा, नालायक व बेईमान लोगों का कहर बरपा है, जिसे झेलने को जनता अभिशप्त है।

नालायक एवं बेईमानों को घर से बुला-बुला कर रखा जाता है

जहां प्राइवेट उद्यमी अपने पूंजीनिवेश से अधिकतम उत्पादन एवं मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिये कहीं से भी बढ़िया से बढ़िया और कुशलतम लोगों को नियुक्त करता है, वहीं राज्य के बिजली प्लांटों का बेड़ा गर्क करने तथा घाटे को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये सरकार चुन-चुन कर निकम्मे, नालायक व बेईमान लोगों को दुगुणे दामों पर घर से बुला-बुला कर लाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण जे.सी.किन्नरा है जो तीसियों बरस तक राज्य के प्लांटों का सत्यानाश करके आठ वर्ष पूर्व चीफ़ इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ था, उसे राज्य के पंचकूला स्थित तमाम प्लांटों के मुख्यालय में बैठा रखा है। सरकार किसी की आये, एमडी कोई बने, किन्नरा का जलवा सदा बरकरार रहता है। मुख्यालय में बैठ कर किन्नरा राज्य भर के तमाम प्लांटों में अपनी कमाश के लोगों का मकड़जाल बुनता रहता है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण पद पर अपने किसी सेवादार प्यादे को नियुक्त कराने का जुगाड़ बनाना किन्नरा का काम है तो बदले में सेवा करना इन प्यादों का काम। इसी लेन-देन के तहत मिगलानी को टेकपरो में लाख रुपया महीना तथा अन्य मौजों की नौकरी किन्नरा ने ही तो दिलाई थी। यूनिट 8 का एसई फ्यूल अनिल दुआ भी तो किन्नरा का ही चहेता था जिसकी वजह से पूरी यूनिट का ही सत्यानाश हो गया। जब मजबूरी में उसे हटाना भी पड़ा तो उसे एसई, ओ एंड एम-2 लगा कर वहीं का वहीं रख लिया और जो एसई, ओ एंड एम-2 पहले से वहां अपना काम ठीक ढंग से कर रहा था, उसे उठा कर भौड़ कलां जिला यमुना नगर भेज दिया गया जिसे सज़ा के तौर पर माना जाता है। सवाल है, सीधे दुआ को भौड़ कलां भेजने में क्या समस्या थी?

यूनिट नंबर 1, 2, 3, व 4 (पीटीपीएस-1) को चलाने के लिये गत चार माह से किन्नरा के एक चहेते चावला को चीफ़ इंजीनियर लगाया गया था, लेकिन जब यूनिट नहीं चली, सत्यानाश बढ़ता ही चला गया तो उसे बड़ी मजबूरी में वहां से हटाया गया। जानकार बताते हैं कि चावला ने मुरम्मत हो रही एक टर्बाइन में जबरदस्ती एक ग़लत एवं ख़राब बैरिंग को फ़िट करने का दबाव जब मुरम्मत करने वाली त्रिवेणी नामक कंपनी पर बढ़ाया तो अपनी बदनामी से बचने के लिये कंपनी ने इसकी शिकायत एमडी से कर दी, जिस पर चावला को वहां से हटा कर पीसी मित्तल को लगाया गया। किन्नरा का ही एक प्यादा वेदप्रकाश अरोड़ा आजकल खेदड़ के प्लांट में नियुक्त है बतौर चीफ़। उस द्वारा क्या-क्या गुल खिलाये जायेंगे, जल्द ही सामने आ जायेंगे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अकेले किन्नरा जैसे अफ़सर ही मलाई खाते रहें और राजनेता खाली बैठे देखते रहें। असल में तो इन नेताओं का कर्त्तव्य है कि वे जनहित में प्लांटों के अफ़सरों पर कड़ी निगरानी रखें, परंतु निगरानी की बजाये वे भी उसमें से अपना हिस्सा-पत्ती के जुगाड़ में रहते हैं। इसके अलावा अपने घर, परिवार, क्षेत्र, बिरादरी के नालायक व निकम्मे लोगों को प्लांटों में भरना ये लोग अपना परम कर्त्तव्य एवं हक मानते हैं।

औरों की तो बात छोड़िये, खुद मुख्यमंत्री हुड्डा ने पीएस मोर नामक एक डिप्लोमाधारक को पानीपत के थर्मल प्लांटों का सेफ़्टी अफ़सर लगवाया हुआ है। इसके नियुक्ति पत्र में मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर लिखवाया है कि इसे एक्सईएन का वेतनमान दिया जाये और यह वेतनमान केवल इसी व्यक्ति के लिये होगा। इस व्यक्ति के बाद इस पद का वेतनमान स्वत: घट कर सामान्य हो जायेगा।

जनता के पैसे से अगर अपने चहेतों का भला होता हो तो हुड्डा क्यों न करें, ऐसे मौके कोई बार-बार थोड़े ही मिलते हैं। विदित है कि जिस व्यक्ति अथवा छोटे कर्मचारी की पीठ पर सीएम का हाथ हो, वह प्लांट में पूरी दादागिरी तो करेगा ही जो कि मोर कर रहा है। चीफ़ या एसई उसके सामने क्या बेचते हैं। सेफ़्टी अफ़सर के नाते मोर का काम लूटने-खाने से अधिक और कुछ नहीं है।

राठौड़ को सजा : क्या न्यायपालिका की जीत?

बीस सालों के बाद के बाद रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ प्रकरण में हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को डेढ़ वर्ष की सजा मिल गई। इसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था की बड़ी जीत के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि कोई भी अपराधी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। लेकिन क्या यह सच है? अगर यह सच होता तो राठौड़ को सजा मिलने में 20 साल नहीं लग जाते। कहा गया है कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर ही होता है। रुचिका गिरहोत्रा मामले में राठौड़ को सजा मिल जाने को मीडिया इस तरह दिखा रहा है कि मानो न्याय व्यवस्था की यह मुकम्मल जीत है। यह ठीक है कि इस प्रकरण में ले-दे कर राठौड़ को सजा मिल गई, पर ऐसे मामले न जाने कितने होते हैं जिसमें किसी को कोई सजा नहीं मिलती। बहुत सारे मामले तो अदालतों में जा भी नहीं पाते। विशेषकर, वैसे मामले जिनमें अपराधी उच्चपदस्थ एवं प्रभावशाली होता है। छेड़छाड़ का मामला ऐसे भी एक बेहद मामूली मामला माना जाता है जिसके लिए अधिकतम दो वर्ष सजा का प्रावधान है। चूंकि रुचिका गिरहोत्रा का मामला मीडिया की दखलंदाजी के कारण एक हाई प्रोफाइल मामला हो गया था, इसलिए इसमें न्यायपालिका को भी कार्रवाई करनी पड़ी। नहीं तो छेड़छाड़ क्या, बलात्कार के मामलों में भी अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती।

रुचिका गिरहोत्रा प्रकरण में राठौड़ को सजा मिलने से सरकार यह दावा कर रही है कि भारतीय न्याय व्यवस्था का कोई जवाब नहीं है। न्याय मंत्री वीरप्पा मोइली भी न्यायपालिका के गुणगान में लग गये हैं। लेकिन एक राठौड़ को सजा मिल जाने से भारतीय न्याय व्यवस्था का चेहरा साफ़-सुथरा नहीं हो जाता। भारतीय न्याय व्यवस्था का चेहरा इतना दागदार है कि एक राठौड़ को सजा मिलने से उसकी छवि पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

- प्रतिनिधि

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06